सं. ग्रो.वि./सोनीपत/16-85/10530.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं. ग्रारगेनो कैमीकल इण्डस्ट्रीज, इण्डस्ट्रीयल एरिया, सोनीपत, के श्रमिक श्री इलम चन्द तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई ग्रौद्योगिक विवाद है;

बौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, भव, भोबोगिक विवाद श्रिधिनियम, 1947 की श्रारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शिक्तयों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी श्रीधसूचना सं 9641-1-श्रम/70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ पठित सरकारी श्रीधसूचना सं 3854-ए. एस. श्रो (ई) श्रम-70/1348, दिनांक 8 मई, 1970, द्वारा उन्त श्रीधिनियम की श्रारा 7 के श्रीधीन गठित श्रम त्यायालय, रोहतक, को विवादशस्त या उससे सुसंगत या उतसे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्विष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रीमक के बीच या तो विवादशस्त मामला है या उक्त विवाद सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :---

क्या श्री इलम चन्द की सेवाग्रों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहुत का हकदार है?

चं बो वि /सोनीपत/15-85/10537.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राग्रे है कि म. अं।रगेनो रवड़ प्रा. लि., इण्डस्ट्रीयल ध्रिया, सोनीपत, के श्रमिक श्री हीरा लाल तथा उसके प्रवन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई मौखेणिक विवाद है;

भौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बाछनीय समझते हैं ;

इसलिए, मन, घोषोपिक विवाद मिसिनियम, 1947, की धारा 10 को उपमारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी मिसिस्वना सं० 9641—1-श्रमं/70/32573, दिनांक 6 नवस्वर, 1970 के साथ पठित सरकारी प्रिवस्तवना सं. 3864—ए,एस.श्रो.(ई)श्रम—70/1348, दिनांक 3 मई, 1970 हारा उक्त प्रवितियम की धारा 7 के मधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादमस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादमस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है :—

क्या श्री हीरा लाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हुकदार है?

सं. ग्रो. वि./सोनीपत/7-84/10544.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की रावे है कि मैं. प्रग्रांशक नगर पालिका, खरखोदा, सोनीपत, के श्रमिक श्री जगबीर सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके हुँबाद लिखित मामले में कोई ग्रीद्योगिक विवाद है ;

ग्रीर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्याय निर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वास्त्रनीय समझते हैं ;

इसिलए, सब, सौद्योगिक विवाद प्रिष्ठित्यम, 1947, की घारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) दारा प्रदान को गई सित्यों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी प्रधिसूचना सं. 9641-1-प्रम-70/32573, दिनांस 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी प्रधिसूचना सं. 3864-ए. एतं. थी. (ई)-श्रम-70/1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त प्रधितियम की घारा 7 के प्रधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवाद प्रस्त या उत्ते पुनंगत या उसने सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय निर्णय हेतु निदिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवाद प्रमानता है था उक्त विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है :---

क्या श्री जगवीर सिंह की सेवाओं का समापन स्थायोचित तथा ठोक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकशर है?

सं गो विव /रोहतक/9-85/10551. — चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै. मोहन सीनिंग मिल, रोहतक, के श्रीमक श्री भीम जिह तथा उसके प्रवश्यकों के बीच इसमें इसके बाद जिल्लित मामले में कोई प्रीक्षोणिक विवाद है;

भीर चूंकि हरियाणा के राज्यवाल विवाद को न्यायित गैय हैतु निर्दिष्ट करना वाछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, मीद्योगिक विवाद मिविनियम, 1947 की घारा 10 की उपवारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की मई अक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी मिविश्वचना सं० 9641-1-अम/70/32573, दिनोक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी श्रिष्ठसूचना सं० 3864—ए. एस. श्रो. (ई)श्रम - 70/1348, दिनांक 8 मई, 1970 कारा उपत्तिशिविषयम की धारा 7 के श्रधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादशस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायिनचंय हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त श्रवन्धकों तथा श्रिमिक ृके बीच या तो विवादशस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है:—-

क्या श्री भीम सिंह की सेवाम्रों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. स्रो. वि./फरीदाबाद/224-84/10558.—चूं कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं. डाबरी वाला स्टील एण्ड इन्जीनियरिंग क० लि॰, प्लाट नं० 136, सैक्टर-24, फरीदाबाद के श्रमिक श्री नवल सिंह तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित के मामले में कोई ग्राद्योगिक विवाद है;

ग्रीर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्याय निर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस, लिए, श्रव श्रौद्योगिक विवाद श्रिष्ठित्यम, 1947 की धारा 10 की उस धारा (1) खंड (ग) द्वारा प्रदान की श्रिष्टियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. \$5415-3-श्रम 68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए श्रिष्टियम ना 11495—जी-श्रम-57/11245, दिनोक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त श्रिष्टित्यम की धारा 7 के श्रिष्ठीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सुसंगत ना विवाद से सुसंगत अथवा के लिये निर्दिंग्ट करते हैं जो कि उवत प्रवादकों तथा श्रिष्टिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है:--

क्यां श्री नवल सिंह की सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 18 मार्च, 1985

सं १ श्री १ वि १ पानीपत/98-84/10934. चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं १ मने जिंग डायरैक्टर, हरियाणा स्टेट माइनर, इरीगेशन टयुबेल कारपोरेशन, चण्डीगढ़, कार्याकारी ग्राभियन्ता, एम. ग्राई. टी. सी., थर्मल पावर प्रोजैक्ट, पानीपत, के श्रीमक श्री सुरत सिंह तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई श्रीद्योगिक विवाद है;

भौर चूकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वाछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, श्रीद्योगिक विवाद श्रविनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)-84-3-अम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त श्रिधिनियम की धारा 7 के श्रधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे संबन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसगत अथवा संवन्धित मामला है:---

क्या श्री सुरत सिंह की सेवाओं का समापन न्यायें। चित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह विस राहत का हकदार है ?

सं. श्रो.वि./हिसार/38-84/10955.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल कि राय है कि में. प्रमुख श्रभियन्ता, पब्लिक हैल्थ हरियाणा; चण्डीगढ़, (2) कार्याकारी, श्रभियन्ता, पब्लिक हैल्थ डिविजन नं० 1, हासी, (3) कार्याकारी श्रभियन्ता, पब्लिक हैल्थ, डि०नं० 2, हिसार, के श्रमिक श्री। रमेश दास तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई श्रीद्योगिक विवाद हैं :

भ्रौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्याय निर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई मिवितयों का प्रयोग करते हुए हिरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम 70/32573, दिनांक 6 मवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए-एस-ओ. (ई)-श्रम/70/1348, दिनांक 8 मई, 1970, द्वारा उक्त अधिनियम है की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादयस्त या उसके सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय निर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादयस्त मामला है या विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :--

नया श्री रमेश दास की सेवाझों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह ॄिकस राहत का हकदार है ?